



INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

ब्रिटिश काल में शिक्षा के विकास का आलोचनात्मक अध्ययन

अनुराज

स्नातकोत्तर (शिक्षा)

सारांश:— भारत में आधुनिक शिक्षा का प्रसार ब्रिटिश शासनकाल में आरंभ हुआ। औपनिवेशिक शासन की स्थापना से पूर्व भारत शिक्षा के क्षेत्र में काफी पिछड़ा हुआ था। केवल कुछ बड़े नगरों और कस्बों में कुछ स्कूल स्थापित थे। ईस्ट इंडिया कंपनी ने शासन के प्रारंभिक दिनों में भारत में शिक्षा के विकास के लिए कोई प्रयत्न नहीं किए क्योंकि आरंभ में वे व्यापारी बनकर आए थे। अतः राजनीति में उनका हस्तक्षेप इतना नहीं था। भारत में उनकी जड़े मजबूत नहीं हुई थी। उन्हें भय था कि कहीं भारतीय जनता विद्रोह करके उन्हें भारत से खदेड़ न दे। उनका भारत में शिक्षा के विकास का उद्देश्य शिक्षित भारतीयों की संख्या बढ़ाना था जिससे छोटे प्रशासनिक पदों पर भारतीयों को नियुक्त किया जा सके। चार्ल्स ग्रांट को आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता माना जाता है। 1813 ई० के चार्टर एक्ट में भारत में वैज्ञानिक शिक्षा के प्रसार के लिए सालाना एक लाख रुपये की राशि का प्रावधान रखा गया। अतः ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत में शिक्षा के प्रसार का वास्तविक कार्य 1813 ई० के बाद किया गया। 1833 ई० के चार्टर एक्ट में शिक्षा हेतु इस रकम को बढ़ाकर सालाना दस लाख रुपये किया गया। इसके बाद समय-समय पर अनेक आयोग/समितियों का गठन किया गया।

बीज शब्द:— औपनिवेशिक शासन, हस्तक्षेप, प्रशासनिक पद, आधुनिक शिक्षा, चार्टर एक्ट।

शिक्षा का माध्यम:— प्राच्य- आंग्ल विवाद:— भारत में दी जाने वाली आधुनिक शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए इस संबंध में लॉर्ड विलियम बैंटिक के शासन काल में 1829 ई० से लेकर 1835 ई० तक एक लम्बा विवाद चलता रहा। लार्ड मैकाले तथा उनके समर्थक यह चाहते थे कि पश्चिमी शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी होना चाहिए। दूसरी ओर H.H. विल्सन एवं उनके समर्थक यह चाहते थे कि शिक्षा का माध्यम प्रादेशिक

भाषाएँ होनी चाहिए। लम्बे विवाद के बाद 1835 ई० में सरकार ने यह निर्णय लिया कि शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी होगा।

अधोमुखी निस्यंदन का सिद्धांतः- यह शिक्षा का सिद्धांत लॉर्ड आकॅलैण्ड ने दिया। इस सिद्धांत के अनुसार अगर उच्च वर्ग को सबसे पहले शिक्षित किया जाए तो इस वर्ग के शिक्षित होने पर छन-छन कर शिक्षा का प्रभाव जन साधारण तक पहुँचेगा।

1854 ई० का शिक्षा का चार्ल्स वुड का डिस्पैचः- वुड डिस्पैच को भारतीय शिक्षा का मैग्नाकार्टा कहा जाता है। इसकी प्रमुख सिफारिशें थी कि सरकार पाश्चात्य शिक्षा, कला, दर्शन, विज्ञान व साहित्य का प्रसार करें। उच्च शिक्षा के लिए माध्यम अंग्रेजी हो किंतु देशी भाषाओं को भी प्रोत्साहित किया जाए। लंदन विश्वविद्यालय के आधार पर कलकत्ता, बम्बई, मद्रास में तीन विश्वविद्यालय स्थापित किए जाए। अध्याक प्रशिक्षण संस्थाओं की स्थापना की जाए। महिला शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए।

हंटर शिक्षा आयोग (1882-1883) :- 1882 ई० में रिपन के काल में W.W. हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग शिक्षा के क्षेत्र में 1854 ई० के बाद हुई प्रगति की समीक्षा के लिए नियुक्त किया गया। इसका कार्य केवल प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा की समीक्षा करना था। इसके प्रमुख सुझाव थेः-

प्राथमिक शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाए तथा प्राथमिक स्कूलों का नियंत्रण जिला और नगर बोर्डों को दिया जाए।

माध्यमिक शिक्षा के दो खण्ड हो। एक में साहित्यिक शिक्षा हो जो विश्वविद्यालय में प्रवेश परीक्षा के लिए विद्यार्थियों को तैयार करें। दूसरी में व्यावसायिक व व्यापारिक जीवन की शिक्षा दी जाए आयोग के सुझाव पर 1882 ई० में पंजाब और 1887 ई० में इलाहाबाद विश्वविद्यालय स्थापित किए गए।

रैले कमीशन 1902ः- 1902 ई० में सर टॉमस रैले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना की गई। इसमें दो अन्य भारतीय सदस्य थे। सैय्यद हुसैन बिलग्रामी, गुरुदास बैनर्जी। इसको केवल विश्वविद्यालयों पर सुझाव देना था। रैले कमीशन के सुझाव के आधार पर 1904 ई० में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया।

इसके मुख्य प्रावधान:-

विश्वविद्यायों में अध्ययन तथा शोध के लिए प्रोफेसरा और लेक्चरर की नियुक्ति करनी चाहिए।

विश्वविद्यालयों के उपसदस्यों की संख्या 50 से कम तथा 100 से अधिक नहीं होनी चाहिए तथा उनका कार्यकाल आजीवन ना होकर 6 वर्ष होना चाहिए।

अशासकीय कॉलेजों पर सरकारी नियंत्रण बढ़ा दिया गया। अतः कर्जन द्वारा शिक्षा में परिवर्तन का उद्देश्य राजनीतिक अधिक शैक्षणिक कम था।

इम्पीरियल लेजिस्लेटिव कौंसिल 1910:- गोपाल कृष्ण गोखले:- 1910 ई० में गोपाल कृष्ण गोखले ने अपना प्रस्ताव रखते हुए 6 से 10 वर्ष की आयु वाले बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा शुरू करने की मांग की।

सैडलर आयोग 1917:- सरकार ने 1917 ई० में कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याओं के अध्ययन हेतु लॉर्डस विश्वविद्यालय के उपकुलपति डॉ० एम. ई. सैडलर की अध्यक्षता में एक आयोग नियुक्त किया। इस आयोग का विचार था कि अगर विश्वविद्यालय की शिक्षा में सुधार करना है तो माध्यमिक शिक्षा का सुधार आवश्यक है। इस आयोग ने 12 वर्ष की स्कूल शिक्षा व इण्टरमिडियट परीक्षा के बाद विश्वविद्यालय में प्रवेश हो। स्नातक पाठ्यक्रम तीन वर्ष का हो। महिला शिक्षा के विकास पर विशेष जोर दिया गया। (1916) मैसूर, (1916) बनारस, (1921) लखनऊ, 1922 ई० में दिल्ली विश्वविद्यालय की स्थापना हुई।

हार्टींग समिति 1929 ई०:- शिक्षा के स्तर में आ रही गिरावट को रोकने के लिए सरकार ने 1929 ई० में सर फिलिप हार्टींग की अध्यक्षता में एक समिति की नियुक्ति की गई। इसने निम्नलिखित सुझाव:- प्राथमिक शिक्षा पर बल किंतु इसे अनिवार्य करने की निंदा की। ग्रामीण छात्रों को मिडिल स्कूल तक की शिक्षा देने के बाद कॉलेजों में प्रवेश के स्थान पर उन्हें व्यावसायिक और औद्योगिक शिक्षा दी जाए। इस समिति की सिफारिश के आधार पर 1935 ई० में "केन्द्रीय शिक्षा सलाहाकर बोर्ड (CABE) का पुर्नगठन किया गया।

मूल शिक्षा की वर्धा योजना:- 1937 ई० में गांधी जी ने अपने पत्र 'हरिजन' में शिक्षा पर एक लेख प्रकाशित किया और वर्धा में एक अखिल भारतीय शिक्षा सम्मेलन में उन्होंने बुनियादी शिक्षा की वर्धा योजना प्रस्तुत की। इस योजना का मूल सिद्धांत यह था कि बच्चों को 7 साल तक मातृभाषा में व अनिवार्य शिक्षा दी जाए। द्वितीय विश्वयुद्ध शुरू होने के कारण वर्धा योजना लागू नहीं हो सकी।

सार्जेण्ट योजना:- 1914 ई०:- इसकी मुख्य सिफारिशें थीं- देश में प्राथमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय स्थापित किए जाएं। 6-11 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा हो। 11-17 वर्ष तक अतिरिक्त शिक्षा व्यवस्था की जाए। इस योजना के अंतर्गत 40 वर्ष के भीतर देश में शिक्षा का पुनर्निर्माण किया जाना था।

ब्रिटिश कालीन शिक्षा का मूल्यांकन:- ब्रिटिश कालीन शिक्षा के मूल्यांकन के संबंध में शिक्षा शास्त्रियों में बड़ा मतभेद है। कुछ लोग इसे अपने गुणों तथा लाभों के कारण एक वरदान मानते हैं और कुछ लोग इसे भारत को लिए एकदम अनुपयुक्त और यहाँ की संस्कृति, सभ्यता, आवश्यकताओं के विपरीत और हानिकारक समझते।

गुण तथा लाभ:- अंग्रेजी माध्यम के कारण भारतीयों को विदेशों के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त हुई। वे रूसों, वालटेयर, स्पेंसर आदि के लेखों से बहुत प्रभावित हुए। पश्चिमी शिक्षा के प्रसार के कारण भारतीयों में प्रचलित अंधविश्वास को दूर किया जा सका। शिक्षा के प्रसार के चलते भारतीयों में राष्ट्रीयता की भावना का तीव्रता से प्रसार हुआ तथा उन्हें स्पष्ट हो गया कि अंग्रेजी सरकार भारतीयों का किस हद तक शोषण कर रही है।

बहुत से शिक्षा शास्त्रियों का मानना है कि ब्रिटिश कालीन शिक्षा से लाभ की अपेक्षा हानि अधिक हुई है। जिनमें से निम्नलिखित मुख्य हैं:-

त्रुटियाँ:- अधिकांश स्कूल जो खुले हुए थे, वे प्राइमरी स्तर तक थे। भारत में मिडिल और हाई स्कूलों की संख्या बहुत कम थी। विद्यार्थियों की शिक्षा नाममात्र थी। इसका कारण यह था कि लोग शिक्षा के महत्व को नहीं समझते थे। उस समय शिक्षा बहुत महंगी थी। अतः इसे धनी वर्ग के लोग ही प्राप्त कर सकते थे। स्त्री शिक्षा बहुत पिछड़ी हुई थी।

निष्कर्ष:-

अतः ब्रिटिश कालीन शिक्षा में उपरोक्त हानियाँ अथवा दोष होते हुए भी हमें यह मानना पड़ेगा कि इस शिक्षा ने भारत में एक नवीन युग का आरंभ किया और भारत को आधुनिक सभ्य देशों की श्रेणी में लाकर खड़ा कर दिया।

संदर्भ ग्रंथ सूची:-

1. Dayal B. : The Development of Modern Indian Education (1953)
2. Mukerjee, S.N. : History of Education in India (1957)
3. Nurullah and Naik: History of Education in India during the British Period (1956).
4. Basu, Aparna: Growth of Education and Political Development in India: (1895-1920).
5. Challenge of Education a Policy Perspective, (1985).
6. Basu, B.D. : History of Education in India Under the Rule of East Indian Company, (Calcutta, 1935).
7. Mahmood, Syed: History of English Education in British India (1781-1893, Aligarh, 1895)

